इंदौर | रविवार | 21 सितम्बर 2025 | वर्ष 65 | अंक 228 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com | twitter.com/Nava_Bharat | fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से
इंदौर 65 वां वर्ष संस्करण

6 पाकिस्तान की सऊदी अरब से रक्षा संधि

6 आसपास को उसी बोली-बानी में कहानियों में दर्ज किया

7 ज्योतिष : एक वैश्विक विश्वास प्रणाली का निरंतर प्रवाह

8 स्मृति मंधाना ने कोहली का रिकार्ड तोड़ा

एच-1बी वीजा : अब देने होंगे 88 लाख रुपये

भारत पर दबाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नया पैंतरा

- नया चार्ज 21 सितंबर के बाद होगा लागू
- तकनीकी दिग्गजों को प्रभावित करेगा

वाशिंगटन, 20 सितंबर. अमेरिका अब एच-1बी वीजा के लिए हर साल एक लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) एप्लिकेशन फीस वसूलेगा.. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किए. नए चार्ज 21 सितंबर से लागू होंगे. ट्रम्प प्रशासन के ताजा फैसले से सबसे ज्यादा भारत पर पड़ने की संभावना है क्योंकि एच-1बी वीजा की सबसे ज्यादा मांग भारत में हो रही है. बड़ी में इंजीनियर्स, डॉक्टर आदि उच्च कौशल क्षमता वाले पेशेवर इस वीजा के जरिये ही अमेरिका जा कर वहां की कम्पनियों के लिए काम करते है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कंपनियों द्वारा एच-1बी आवेदकों को प्रायोजित करने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि को बढ़ाकर एक लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका उन उच्च कुशल प्रतिभाओं को लाए, जिनकी जगह अमेरिकी कर्मचारी नहीं ले सकते. घोषणा में कहा है, कार्यक्रम के व्यवस्थित दुरुपयोग के माध्यम से अमेरिकी कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापन ने हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा, दोनों को कमजोर किया है.

आदेश के अनुसार विशेष व्यवसायों में काम करने के लिए एच-1बी वीजा धारक विदेशी नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, सिवाय उन आवेदकों के जिनकी याचिकाओं में उनके नियोक्ता द्वारा छह अंकों का भुगतान शामिल है. यह प्रवेश प्रतिबंध उन विदेशी नागरिकों पर लागू होगा, जो घोषणा की तिथि, 21 सितंबर के बाद अमेरिका में प्रवेश कर रहे हैं या प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 से 2023 के बीच स्वीकृत वीजा में 73.7 फीसदी वीजा भारतीयों को मिले थे। चीन 16 फीसदी के साथ दूसरे स्थान पर था। कनाडा 3% के साथ तीसरे स्थान पर, उसके बाद ताइवान (1.3%), दक्षिण कोरिया (1.3%), मैक्सिको (1.2%) और नेपाल, ब्राजील, पाकिस्तान और फिलीपींस (सभी 0.8%) हैं। इस नवीनतम नीति से कंपनियों के लिए विदेशी प्रतिभाओं को नियुक्त करने की लागत में भारी वृद्धि होगी.

2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे

एच-1बी वीजा के नियमों में बदलाव से 2 लाख से ज्यादा भारतीय प्रभावित होंगे. साल 2023 में एच-1बी वीजा लेने वालों में 1 लाख 91 हजार लोग भारतीय थे. ये आंकड़ा 2024 में बढ़कर 2 लाख 07 हजार हो गई. भारत की आईटी/टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को एच-1बी पर अमेरिका भेजती हैं. हालांकि, अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा. 71 प्रतिशत भारतीय एच-1बी वीजा धारक हैं और यह नई फीस उनके लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है. खासकर मिड-लेवल और एंट्री-लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलना मुश्किल होगा.

राहुल गांधी ने साधा निशाना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उनकी तरफ से कांग्रेस नेता पर यह वार ऐसे समय किया गया है जब अमेरिका ने एच-1बी वीजा नियमों को सख्त कर दिया है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर पीएम मोदी की आलोचना की.

फैक्ट फाइल

- **पंजीकरण शुल्क :** वित्तीय वर्ष 2025 के लिए $10 और वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 215, जिसे यूएससीआईएस प्रत्येक लाभार्थी के लिए लेता है.
- **आधार दाखिला शुल्क :** अधिकांश एच-1बी याचिकाओं के लिए $ 460, चयन होने के बाद भुगतान किया जाता है.
- **एंटी फ्रॉड शुल्क :** शुरुआती एच-1बी आवेदनों के लिए 500.
- **बड़े नियोक्ताओं के लिए अतिरिक्त शुल्क :** उन नियोक्ताओं पर अतिरिक्त $4,000 शुल्क जिनके कार्यबल का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा एच-1बी या एल-1 वीजा पर है.

भारत पर पड़ने वाले असर का अध्ययन जारी : एमईए

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वह एच 1 बी वीजा की फीस में भारी बढ़ोत्तरी की अमेरिकी सरकार की घोषणा के भारत पर पड़ने वाले असर का अध्ययन कर रहा है. उन्होंने कहा, सरकार ने अमेरिकी एच 1 बी वीजा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्ट देखी हैं. इसके पूर्ण निहितार्थों का अध्ययन सभी संबंधित पक्षों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारतीय उद्योग भी शामिल है, जिसने एच1 बी कार्यक्रम से संबंधित कुछ धारणाओं को स्पष्ट करते हुए एक प्रारंभिक विश्लेषण पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

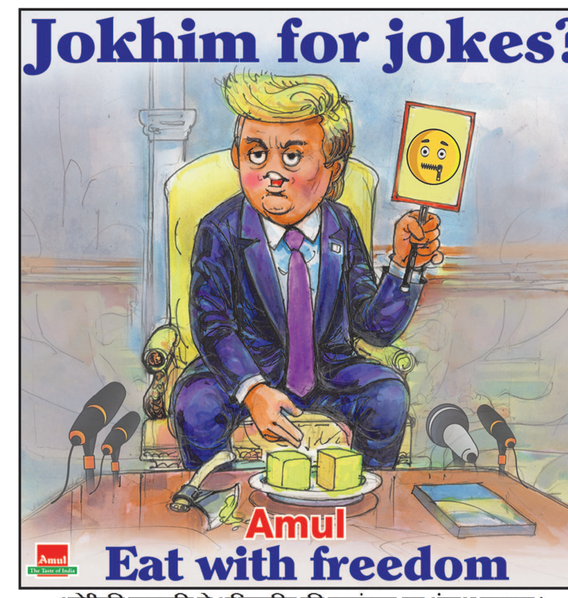

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया!

मोहनलाल को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार

नई दिल्ली 20 सितंबर. मलयालम फिल्मों के जाने- माने अभिनेता मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को मोहनलाल को यह पुरस्कार दिये जाने की घोषणा करते हुए कहा कि अभिनेता को यह सम्मान मंगलवार को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा. मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक पोस्ट में कहा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर भारत सरकार को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

एक नजर में

यूरोप के कई एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक

नई दिल्ली. यूरोप के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक की खबरें सामने आई हैं. इसके चलते एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. साइबर अटैक ने चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम को ठप हो गया. इस हमले का सबसे ज्यादा असर हीथ्रो, ब्रसेल्स और बर्लिन एयरपोर्ट पर दिखा है. उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन के हजारों यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गईं.

उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस की बैठक

नई दिल्ली. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के चयन को लेकर शनिवार को यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कई उम्मीदवारों के नाम तथा अन्य महत्वपूर्ण विंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी नेता अजय माकन की अध्यक्षता में हुई छानबीन समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तथा स्थिति पर चर्चा हुई। उनका कहना था कि शुक्रवार को भी समिति की बैठक हुई थी, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। बैठक में नहीं पहुंचने वाले नेताओं ने बताया कि जब तक गठबंधन के साथ सीटों का बंटवारा नहीं होता.

समुद्र के नीचे देश की पहली सुरंग का निर्माण पूरा

नई दिल्ली. रेलवे ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के घनसोली और शिलफाटा में किए गए सुरंग निर्माण को बड़ी सफलता करार देते हुए कहा है कि यह देश की पहली परियोजना है जिसके तहत समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण किया गया है. आधिकारिक मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना में की यह भारतीय इंजीनियरिंग की ऐतिहासिक उपलब्धि 4.8 किलोमीटर लंबे सुरंग खंड पर हासिल की गई है. इससे जुड़े इंजीनियरों के अनुसार घनसोली और शिलफाटा की ओर से एक साथ खुदाई का काम शुरु किया गया.

जज शक्ति का प्रयोग जिम्मेदारी से करें

सीख : सीएटी के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन में बोले सीजेआई

नई दिल्ली 20 सितम्बर. देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने शनिवार को न्यायपालिका की भूमिका, जजों के आचरण और न्याय व्यवस्था की मजबूती पर एक अहम संदेश दिया. दिल्ली में आयोजित सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (सीएटी) 2025 के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन में बोलते हुए सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका के पास अपरिमित शक्ति है, लेकिन उसका उपयोग विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए.

> सीजेआई गवई ने न्यायाधीशों और वकीलों के रिश्ते को एक रथ के दो पहिए बताया और कहा कि यदि दोनों साथ चलेंगे, तभी न्याय व्यवस्था आगे बढ़ सकती है. वकील और जज एक-दूसरे के पूरक हैं.

सीजेआई ने कहा - हमारे सामने जो वादी आता है, वह उम्मीद लेकर आता है कि उसे न्याय मिलेगा. ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम निष्पक्ष और संवेदनशील होकर निर्णय लें. हमारे पास शक्ति है, लेकिन उसे केवल सही दिशा में ही प्रयोग करना चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह बातें किसी आलोचना के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सुधार के अवसर के रूप में कही जा रही हैं. उनका उद्देश्य है कि ट्रिब्यूनल और पूरी न्याय व्यवस्था अधिक विश्वसनीय और मजबूत बने.

'सोलर-प्लस-स्टोरेज' परियोजना बनी मिसाल

- मुरैना 'सोलर-प्लस-स्टोरेज' परियोजना ने ग्रीन ऊर्जा और स्टोरेज को दी नई दिशा : मुख्यमंत्री

भोपाल 20 सितंबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है. मुरैना की यह परियोजना 'सेवा पखवाड़ा' के दौरान राष्ट्र को समर्पित है.

उन्होंने कहा कि मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना से पूरे देश में ग्रीन ऊर्जा उत्पादन और स्टोरेज की नई राह खुलेगी.

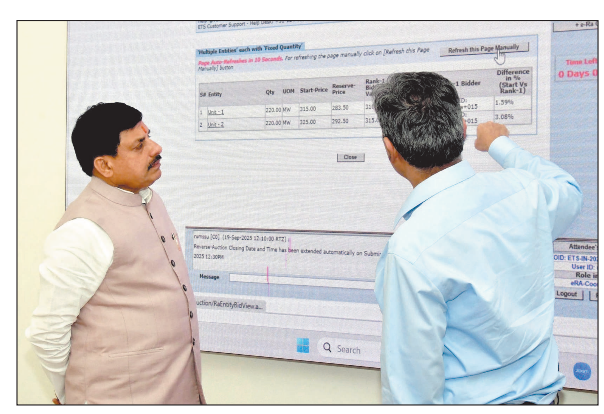

मुख्यमंत्री ने मुरैना परियोजना में प्राप्त की गई सफलता के आधार पर लंबे समय की ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए संकल्प व्यक्त किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परियोजना में प्राप्त किया गया कम टैरिफ प्रदर्शित करता है कि नवकरणीय ऊर्जा भी डिस्कॉम के लिए अधिक किफायती हो सकता है.

परियोजना की संरचना और क्षमता

मुरैना सोलर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया गया है, जिसने पहले भी प्रतिष्ठित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित किया है. मुरैना परियोजना से उत्पादित बिजली राज्य द्वारा खरीदी जाएगी. मुरैना सोलर पार्क में 2 यूनिट स्थापित की जा रही हैं, प्रत्येकइकाई से तीनों चरणों में 220 मेगावॉट क्षमता ऊर्जा का उत्पादन होगा.

मिग-21 को सेना कहेगी अलविदा

नई दिल्ली 20 सितंबर. छह दशक से भी लंबे समय तक भारत की हवाई सीमाओं के प्रहरी रहे और 1965 की लड़ाई से लेकर अभी तक के सभी छोटे-बड़े सैन्य अभियानों में शौर्य और पराक्रम की गाथा लिखने वाले मिग-21 यानी मिकोयान-गुरेविच-21 लड़ाकू विमान को आगामी 26 सितम्बर को वायु सेना अलविदा कहने जा रही है.

पिछले दशक तक भारतीय वायु सेना की रीढ़ और उसके लड़ाकू विमान के बेड़े की शान रहा यह विमान सैन्य विमानन के क्षेत्र में शौर्य और पराक्रम की छह दशक से भी लंबी ऐसी विरासत छोड़ जाएगा, जिसे भूला पाना नामुमकिन होगा. मिग-21 ने अपनी ताकत, फुर्ती और सटीक हमलों से भारतीय वायु सेना की मारक क्षमता और उसकी शक्ति को नया आयाम दिया.

सेना ने चार आतंकियों को घेरा, जवान शहीद

- जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बड़ा एनकाउंटर
- दूदू बसंतगढ़ की पहाड़ियों पर जैश के 4 आतंकी घिरे

श्रीनगर 20 सितंबर. जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में शुक्रवार देर रात से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. बताया जाता है कि दूदू बसंतगढ़ की पहाड़ियों पर जैश के 3 से 4 आतंकवादियों को संयुक्त बलों ने घेर लिया, जिसके बाद से लगातार गोलीबारी जारी है.

इस गोलीबारी में एक जवान घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका. अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया था.

विशिष्ट सूचना के आधार पर, सेना, विशेष अभियान समूह (एसओजी) और पुलिस ने सोजधार के ऊंचाई वाले इलाके से लगे दूदू पुलिस थाना क्षेत्र में एक अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप मुठभेड़ हुई. जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मुठभेड़ जारी है. एसओजी, पुलिस और भारतीय सेना की संयुक्त टीमें मौके पर मौजूद हैं.

दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है : पीएम मोदी

- गुजरात को 34,200 करोड़ रुपए की सौगात दी

भावनगर, 20 सितंबर (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में 34,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शनिवार को उद्घाटन और शिलान्यास कर कहा कि भारत आज विश्व-बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा, दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है. सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है, तो वह है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता. यहीं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है. हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को, निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा. हमें ये बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता, उतनी ज्यादा देश की विफलता, विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा. हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे, तो हमारा आत्म-सम्मान भी चोटिल होगा. 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते, देश के विकास के संकल्प को हम दूसरों की निर्भरता पर नहीं छोड़ सकते, हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते.

मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का किया वर्चुअली इनॉगरेशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर से वर्चुअली बैलार्ड पियर पर अत्याधुनिक मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इनॉगरेशन किया. यह देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है, जिसे क्रूज भारत मिशन के तहत विकसित किया गया है. करीब 4.15 लाख वर्ग फुट में फैला यह टर्मिनल हर साल 10 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है. इस टर्मिनल पर एक साथ 5 क्रूज शिप खड़े हो सकेंगे. यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें 72 चेक-इन और इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं.

समारोह | प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्र का आईआईएम मुंबई दीक्षांत समारोह में संबोधन

'सुधार, प्रदर्शन व परिवर्तन' विकसित भारत की कुंजी

मुंबई, 20 सितंबर. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्र ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) मुंबई के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के तहत देश साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्री प्राप्ति पर बधाई देते हुए कहा कि सफलता व्यक्तिगत प्रयास के साथ परिवार, शिक्षक और सहकर्मियों के सहयोग का भी परिणाम है. डॉ. मिश्र ने वैश्विक परिदृश्य की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कोविड-19, व्यापार युद्धों, जलवायु परिवर्तन व तकनीकी व्यवधानों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है.

जहां 100 से अधिक यूनिकॉर्न और 1.9 लाख स्टार्टअप कार्यरत हैं। साथ ही उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय रिसर्च कोष, इंडिया एआई मिशन और डीप टेक फंड जैसे नवाचारोन्मुख सरकारी प्रयासों को रेखांकित किया।

> मानव संसाधन विकास पर बोलते हुए डॉ. मिश्र ने कहा कि केवल तकनीकी दक्षता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण, टीमवर्क, नैतिकता और पारदर्शिता भी जरूरी हैं. उन्होंने स्नातकों से निरंतर सीखते रहने का आग्रह किया और कहा कि बदलते समय में ज्ञान जल्दी अप्रचलित हो जाता है. प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि 2014 से वरिष्ठ अधिकारियों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शी और विश्वसनीय बदलाव किए गए हैं। 2016 में बहु-स्रोत प्रतिक्रिया प्रणाली लागू की गई, जिससे निर्णय लेने, स्वामित्व और ईमानदारी जैसे गुणों का आकलन होता है. साथ ही ग्रुप बी और सी पदों के लिए साक्षात्कार खत्म किए जाने से चयन प्रक्रिया निष्पक्ष हुई. उन्होंने मिशन कर्मयोगी को प्रशासनिक क्षमता निर्माण का परिवर्तनकारी कदम बताते हुए कहा कि आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से अब तक 1.3 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता जुड़े हैं और 5 करोड़ से ज्यादा पाठ्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं. यह दुनिया की सबसे बड़ी शासन-शिक्षण प्रणाली है.